

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 107

जिसका उत्तर, 03 फरवरी, 2020/14 माघ, 1941 (शक) को दिया गया

बैंक ऋणों का पुनर्गठन

107. श्री दीपक अधिकारी (देव):

श्री प्रताप सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उद्योगों/कॉर्पोरेट घरानों से संबंधित बैंकों द्वारा माफ किए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है और उसके बैंक-वार और कंपनी-वार क्या कारण हैं;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान उन कंपनियों का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है जिनके ऋणों का पुनर्गठन किया गया है और इसकी निबंधन एवं शर्तें क्या हैं;
- (ग) क्या सरकार का विचार किसान ऋणों का भी पुनर्गठन करने का है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का उनके वैश्विक परिचालन में कुल सकल अग्रिम जो दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 25,03,431 करोड़ रुपए था दिनांक 31.03.2014 को बढ़कर 68,75,748 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के पाए गए मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आक्रामक उधार पद्धति, इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी/कुछेक मामलों में भ्रष्टाचार तथा आर्थिक मंदी है। परिशुद्ध एवं पूर्णतः प्रावधानीकृत बैंक तुलन-पत्र के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) से अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) में अत्यधिक वृद्धि का पता चला। एक्यूआर तथा बैंकों द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, दबावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में अनुमानित हानियों, जिनके लिए पुनर्संरचित ऋणों के लिए प्रदान किए गए लचीलेपन के अंतर्गत पूर्व में प्रावधान नहीं किए गए थे, के लिए प्रावधान किए गए। इसके अलावा, दबावग्रस्त ऋणों की पुनर्संरचना संबंधी ऐसी सभी योजनाओं को वापस ले लिया गया था। वैश्विक परिचालनों पर आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, मुख्यतया दबावग्रस्त आस्तियों की एनपीए के रूप में पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, एससीबी का सकल एनपीए जो दिनांक 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार, 3,23,464 करोड़ रु. था, दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 10,36,187 करोड़ रु. हो गया एवं एनपीए की पारदर्शी पहचान,

समाधान, पुनर्पूजीकरण और सुधार की सरकार की कार्यनीति के परिणामस्वरूप दिनांक 30.9.2019 की स्थिति के अनुसार 1,01,267 करोड़ रु. से कम होकर 9,34,920 करोड़ रु. करोड़ रूपए हो गया है।

आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुप्रयोज्य ऋणों सहित वैसे ऋणों, जिनको चार वर्ष पूरा होने पर पूर्ण प्रावधानी करके उन्हें बट्टे खाते डालकर संबंधित बैंक के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है। बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों और अपने बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अपने तुलन-पत्र को परिशुद्ध करने, कर लाभ प्राप्त करने और पूँजी को इष्टतम बनाने के लिए अपनी नियमित प्रक्रिया के रूप में अनुप्रयोज्य आस्तियों को स्वयं बट्टे खाते डालने के प्रभाव का मूल्यांकन/विचार करते हैं। चूंकि बट्टे खाते डाले गए ऋणों के उधारकर्ता पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी बने रहते हैं और बट्टे खाते डाले गए ऋण खातों में उधारकर्ता से देयराशियों की वसूली की प्रक्रिया चलती रहती है, बट्टे खाते डाले जाने से उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता है। विगत तीन वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम छमाही तक के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योगों से संबंधित बट्टे खाते डाले गए अनर्जक आस्तियों का बैंक-वार ब्यौरा अनुबंध में है। बट्टे खाते डाले गए ऋणों और पुनर्गठित ऋणों के कंपनी-वार ब्यौरे के संबंध में आरबीआई ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ड. के उपबंधों के तहत, आरबीआई को ऋण संबंधी सूचना को प्रकट करने से प्रतिबंधित किया गया है। धारा 45ड. यह सूचना प्रदान करती है कि बैंक द्वारा प्रस्तुत ऋण संबंधी सूचना को गोपनीय माना जाएगा और इसे न तो प्रकाशित ना ही प्रकट किया जाएगा।

किसानों के ऋणों के पुनर्गठन के संबंध में, यह सूचित किया गया है कि आरबीआई ने दिनांक 17.10.2018 के मुख्य दिशानिर्देश के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले राहत उपायों पर स्थायी दिशानिर्देश जारी किया है। इन दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा कृषि ऋणों और सावधि ऋणों के पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण, नए ऋण प्रदान करना, प्रतिभूति और मार्जिन शर्तों में छूट, अधिस्थगन आदि शामिल हैं और जिस समय संबंधित जिला प्राधिकारी द्वारा आपदा की घोषणा की जाती है, ये बिना किसी रुकावट के उसी समय से स्वतः लागू हो जाता है। बैंकों द्वारा राहत उपाय आरंभ करने संबंधी बैंचमार्क 33% फसल हानि है। आरबीआई ने बैंकों को पुनर्गठित ऋणों के लिए अतिरिक्त संपार्शिक प्रतिभूति के लिए दबाव नहीं देने का सुझाव दिया है।

अनुबंध

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योगों से संबंधित बट्टे खाते डाले जाने के कारण एनपीए में कटौती राशि करोड़ रुपए में

बैंक	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	एच1 वित्तीय वर्ष 2019-20	वैशिक परिचालनों के संबंध में आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) बैंकों का अग्रिम जो दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 25,03,431 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2014 को बढ़कर 68,75,748 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के पाए गए मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आक्रामक उधार पदधति, इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी/ कुछेक मामलों में भ्रष्टाचार तथा आर्थिक मंदी है। वर्ष 2015 में आरम्भ एक्यूआर तथा बैंकों द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप दबावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा इनके लिए प्रावधान किए गए। पहचान, समाधान, पुनर्पूर्तीकरण और सुधार की सरकार की कार्यनीति के परिणामस्वरूप अब दिनांक 30.9.2019 की स्थिति के अनुसार, 9,34,920 करोड़ रुपए घटकर 1,01,267 करोड़ रुपए हो गया है।
एबी बैंक लिमिटेड	-	-	9	-	आरबीआई के द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुप्रयोज्य ऋणों सहित उन ऋणों, जिनके चार वर्ष पूरा होने पर पूर्ण प्रावधानीकरण किया गया है, को बट्टे खाते डालकर संबंधित बैंक के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है। बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुप्रयोज्य ऋणों सहित उन ऋणों, जिनके चार वर्ष पूरा होने पर पूर्ण प्रावधानीकरण किया गया है, को बट्टे खाते डालकर संबंधित बैंक के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है। बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों और अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अपने तुलन-पत्र को परिशुद्ध करने, कर लाभ और पूँजी को इष्टतम बनाने के लिए अपनी नियमित प्रक्रिया के रूप में अनुप्रयोज्य आस्तियों को स्वयं बट्टे खाते डालते हैं। चूंकि बट्टे खाते डाले गए ऋणों के उधारकर्ता अपनी नियमित प्रक्रिया का दायित्व बना रहता है और बट्टे खाते डाले गए ऋण खातों में उधारकर्ता से देयराशियों की वसूली की प्रक्रिया चलती रहती है, बट्टे खाते डाले जाने से उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता है।
अबू धाबी कॉर्पोरेशन बैंक पीजेएससी	26	26	22	-	
इलाहाबाद बैंक	3,466	3,947	4,941	6,447	
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प	-	17	53	39	
आंध्रा बैंक	3,197	4,000	5,468	6,094	
एक्सिस बैंक लिमिटेड	4,206	8,569	12,714	15,133	
बंधन बैंक लिमिटेड	-	26	92	128	
बैंक ऑफ अमेरिका, नेशनल एसोसिएशन	14	25	25	25	
बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी.एस.सी.	5	58	-	-	
बैंक ऑफ बडौदा (बीओबी)	3,597	7,944	10,413	21,602	
देना बैंक	1,720	2,023	4,390	Amalgamated with BoB	
विजया बैंक	2,317	3,659	4,561		
बैंक ऑफ इंडिया	8,633	14,226	18,546	16,010	
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	824	1,762	4,474	4,821	
बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	101	160	26	-	
बार्कलेज बैंक पीएलसी	455	459	459	459	
केनरा बैंक	9,442	16,244	31,515	25,388	
कैथोलिक सीरियन बैंक लि	187	190	341	393	
सेंटल बैंक ऑफ इंडिया	6,780	8,843	15,368	15,514	
सिटी बैंक एन.ए.	74	97	116	134	
सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड	160	258	333	320	
कोऑपरेटिव राबोबैंक यू.ए.	-	206	-	-	
कॉर्पोरेशन बैंक	6,782	13,838	18,266	19,358	
क्रेडिट एचीकोल कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक	263	72	251	-	
डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड	1,985	2,419	2,642	2,642	
डीसीबी बैंक लिमिटेड	29	34	71	117	
डियू बैंक एजी	108	123	274	284	
दोहा बैंक क्यू.पी.एस.सी.	242	-	-	-	
फेडरल बैंक लिमिटेड	789	638	730	875	
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	848	989	1,071	1,746	
हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्प. लिमिटेड	86	-	-	-	
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	8,328	12,366	17,461	18,457	
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	6,388	17,498	28,437	30,020	
आईडीएफसी फस्ट बैंक लिमिटेड	1,371	956	2,530	3	
इंडियन बैंक	1,712	2,661	5,432	5,326	
इंडियन ओवरसीज बैंक	2,988	5,440	8,312	16,857	
इंडसइंड बैंक लि	614	744	916	1,133	
जम्म एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	651	2,508	1,655	1,677	
जेपीमोर्गन चेस बैंक नेशनल एसोसिएशन	270	271	287	293	
कर्नाटक बैंक लि	733	939	1,379	1,926	
करुर वैश्य बैंक लि	712	903	1,240	1,137	

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	958	1,194	1,266	1,466	
लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड	274	361	619	430	
एमयूएफजी बैंक लिमिटेड	98	-	-	-	
नैनीताल बैंक लि	-	11	11	11	
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	3,743	8,149	10,805	11,575	
पंजाब एंड सिंध बैंक	1,013	1,217	2,592	2,575	
पंजाब नैशनल बैंक	25,899	30,590	38,576	41,746	
आरबीएल बैंक लिमिटेड	60	71	75	192	
एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड	103	121	-	-	
साउथ इंडियन बैंक लि	566	694	553	944	
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	-	-	872	479	
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)	55,958	79,999	1,24,165	1,45,239	
स्टेट बैंक ऑफ हैंदराबाद	2,833				
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	4,077				Merged into SBI
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	1,628				
सिंडीकेट बैंक	3,164	4,489	7,626	7,985	
तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लिमिटेड	357	861	1,073	1,064	
दि धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	241	203	204	204	
दि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड पीएनसी	-	49	115	-	
यूको बैंक	4,718	5,503	7,223	10,247	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,795	2,997	3,864	7,853	
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2,134	4,017	9,383	1,130	
येस बैंक लि.					
	355	902	1,261	1,580	

वैश्विक परिचालनों के संबंध में आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) बैंकों का अग्रिम जो दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 25,03,431 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2014 को बढ़कर 68,75,748 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के पाए गए मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आक्रामक उधार पद्धति, इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी/ कुछेक मामलों में अष्टाचार तथा आर्थिक मंदी है। वर्ष 2015 में आरम्भ एक्यूआर तथा बैंकों द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप दबावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा इनके लिए प्रावधान किए गए। पहचान, समाधान, पुनर्पूजीकरण और सुधार की सरकार की कार्यनीति के परिणामस्वरूप अब दिनांक 30.9.2019 की स्थिति के अनुसार 9,34,920 करोड़ रुपए घटकर 1,01,267 करोड़ रुपए हो गया है।

आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुप्रयोज्य ऋणों सहित उन ऋणों, जिनके चार वर्ष पूरा होने पर पूर्ण प्रावधानीकरण किया गया है, को बट्टे खाते डालकर संबंधित बैंक के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है। बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों और अपने बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अपने तुलन-पत्र को परिशुद्ध करने, कर लाभ और पूँजी को इष्टतम बनाने के लिए अपनी नियमित प्रक्रिया के रूप में अनुप्रयोज्य आस्तियों को स्वयं बट्टे खाते डालते हैं। चूंकि बट्टे खाते डाले गए ऋणों के उधारकर्ताओं पर पुनर्भुगतान का दायित्व बना रहता है और बट्टे खाते डाले गए ऋण खातों में उधारकर्ता से देयराशियों की वसूली की प्रक्रिया चलती रहती है, बट्टे खाते डाले जाने से उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता है।

स्रोत: आरबीआई
